इनबेसेगरन और अन्य

बनाम

एस.नटराजन (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधि

(सिविल अपील संख्या 4215-4216/2007 इत्यादि)

29 अक्टूबर, 2014

[एम.वाई. इकबाल और शिव कीर्ति सिंह, जेजे.]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908:

ओ 2 आर 2 – द्वितीय वाद निषेध - वादी ने प्रतिवादियों को उसके कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा के लिए वाद दायर किया है -उसी संपत्ति के संबंध में बिक्री के अनुबंध के विशिष्ट अनुपालना के लिए वादी द्वारा दूसरा वाद दायर किया गया - दो मुकदमे और उनमें उल्लिखित वाद हेतुक यह दर्शाता है कि वाद हेतुक और मांगी गई राहतें काफी अलग हैं और समान नहीं हैं- इसलिए, ओ. 2 आर 2 के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

'वाद हेतुक' - समझाया गया।

पूर्ववर्तीः

निर्णय का अनुपात - उस मामले के तथ्यों की पृष्ठभूमि में समझा जाना चाहिए।

अपीलः

प्रथम अपील - उच्च न्यायालय, प्रथम अपील में तथ्यों का अंतिम न्यायालय होने के नाते, इसके द्वारा तैयार किए गए सभी बिंदुओं पर निर्णय लेना आवश्यक है - मामला उच्च न्यायालय को उसके द्वारा तैयार किए गए सभी बिंदुओं पर अपने निष्कर्ष दर्ज करके अपील पर निर्णय लेने के लिए भेजा गया।

अपीलों को निस्तारित करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1.1. प्रथम वाद वादी-अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी, उसके एजेंटों और नौकरों को वादी द्वारा वाद की संपत्ति के कब्जे और आनंद में अतिक्रमण करने का प्रयास करके या किसी भी अन्य तरीके से हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा देने के लिए दायर किया गया। अन्य तथ्यों के अलावा, यह दलील दी गई कि बिक्री समझौते के अनुसरण में वादी ने प्रत्यर्थी से वाद भूखंड पर कब्जा कर लिया और निर्माण शुरू कर दिया। वाद मुख्य रूप से वाद हेतुक पर दायर किया गया था जो तब उत्पन्न हुआ जब प्रत्यर्थी ने वादी के श्रमिकों को भगाकर वाद की संपत्ति पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया और प्रत्यर्थी जबरन और गैरकानूनी तरीके से वाद की संपत्ति पर कब्जा करने की व्यवस्था कर रहा था। [पैरा 16] [1213-सी, डी, जी, एच]

1.2. वादी द्वारा दायर बाद के मुकदमे में, बिक्री के लिए समझौते के विशिष्ट अनुपालना के लिए एक डिक्री का दावा अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर किया गया कि पहले के मुकदमे में प्रत्यर्थी ने बचाव किया था कि वादी द्वारा बिक्री समझौते को कथित तौर पर छोड़ दिया गया था या वादी द्वारा छोड़ दिया गया था। वाद हेतुक, जैसा कि वादी ने बाद के मुकदमे में निवेदन किया था, तब उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी-प्रत्यर्थी ने हाउसिंग बोर्ड द्वारा उसके पक्ष में किए गए हस्तांतरण का खुलासा किया और अंततः जब प्रतिवादी बिक्री समझौते के अपने हिस्से को पूरा नहीं करने का इरादा प्रदर्शित कर रहा था और अधिवक्ता के नोटिस के जवाब में प्रतिवादी ने झूठा आरोप लगाया और अनुबंध के अनुसार विक्रय पत्र निष्पादित करने से इनकार कर दिया। [पैरा 17] [1214-बी-सी]

1.3. इस प्रकार, दोनों मुकदमों में दलीलों का अवलोकन और उसमें उल्लिखित वाद हेतुक दिखाई देंगे कि वाद हेतुक और मांगी गई राहत काफी अलग हैं और समान नहीं हैं। [पैरा 18] [1214-डी]

विर्गो इंडस्ट्रीज (इंग) (पी) लिमिटेड बनाम वेंचरटेक सोलुसंस (पी) लिमिटेड 2012 (7) एससीआर 933 = (2013) 1 एससीसी 625- अप्रयोज्य।

1.4. यह सुस्थापित है कि किसी भी निर्णय का अनुपात उस मामले तथ्यों की पृष्ठभूमि में समझा जाना चाहिए। [पैरा 30] [1224-एच]

भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड और अन्य बनाम एन.आर.वैरामणि और एक अन्य 2004 (4) पूरक एससीआर 923 = (2004) 8 एससीसी 579- पर निर्भरता।

1.5. वाद हेतुक में तथ्यों का एक समूह होता है जो वादी के लिए न्यायालय से राहत पाने के लिए क्रम में साबित करना आवश्यक होगा। जब दो मुकदमों के लिए कार्रवाई के कारण अलग-अलग और अलग-अलग हों और दोनों मुकदमों में राहत का समर्थन करने वाले साक्ष्य भी अलग-अलग हों तो 02, आर 2 सीपीसी के प्रावधान लागू नहीं होंगे। [पैरा 19] [1214-ई-एफ]

गुरबक्स सिंह बनाम भुरालाल 1964 एससीआर 831 = एआईआर 1964 एससी 1810- अनुसरण किया गया।

केवल सिंह बनाम लाजवंती, 1980 (1) एससीआर 854 = (1980) 1 एससीसी 290; देव राम बनाम ईश्वर चंद, 1995 (4) पूरक एससीआर 369 =(1995) 6 एससीसी 733; सिद्रमप्पा बनाम राजशेट्टी और अन्य 1970 (3) एससीआर 319 = एआईआर (1970) एससी 1059; एम.पी. राज्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य 1977 (2) एससीआर 555 = (1977) 2 एससीसी 288- पर भरोसा किया।

मोहम्मद खलील खान और अन्य बनाम महबूब अली मियां और अन्य, एआईआर (36) 1949 प्रिवी काउंसिल 78-निर्दिष्ट।

2.1. प्रथम अपील में तथ्यों का अंतिम न्यायालय होने के नाते, उच्च न्यायालय को उसके द्वारा तैयार किए गए सभी बिंदुओं पर निर्णय लेना आवश्यक है। वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय ने, हालांकि विचार और निर्णय के लिए विभिन्न बिंदुओं को तैयार किया है, लेकिन अन्य बिंदुओं पर सही परिप्रेक्ष्य में विचार नहीं किया है। इसे ध्यान में रखते हुए, मामले को उच्च न्यायालय द्वारा तैयार किए गए अन्य बिंदुओं पर विचार करने और निर्णय लेने के लिए वापस भेजने की आवश्यकता है। [पैरा 34] [1226-सी-डी]

2.2. उच्च न्यायालय ने बिंदु संख्या 4 के विरुद्ध जो फैसला सुनाया, उसमें यह कहा गया कि मुकदमा सीपीसी आदेश 02, नियम 2 के तहत वर्जित था, खारिज कर दिया गया है। मामले को उसके द्वारा तैयार किए गए अन्य बिंदुओं पर निष्कर्ष दर्ज करके अपील पर निर्णय लेने के लिए उच्च न्यायालय को वापस भेजा जाता है। [पैरा 35] [1126-ई]

लक्ष्मी उर्फ भाग्यलक्ष्मी और एक अन्य बनाम ई. जयराम (मृत) द्वारा एलआर, 2013 (1) एससीआर 794 = (2013) 9 एससीसी 311-उद्धृत किया गया।

मामला कानून संदर्भः

(1964) 7 एससीआर 831	अनुसरण किया	पैरा 13
1980 (1) एससीआर 854	भरोसा किया	पैरा 13
2013 (1) एससीआर 794	उद्धत किया	पैरा 13
2012 (7) एससीआर 933	अप्रयोज्य	पैरा 14
एआईआर (36) 1949 प्रिवी कौंसिल 78	संदर्भित किया	पैरा 20

1995 (4) पूरक एससीआर 369 भरोसा किया पैरा 23

1970 (3) एससीआर 319 भरोसा किया पैरा 24

1977 (2) एससीआर 555 भरोसा किया पैरा 25

2004 (4) पूरक एससीआर 923 भरोसा किया पैरा 31

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 4215-4216/2007

मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा ए.एस.संख्या 666/2001 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 30.04.2004 से उत्पन्न।

साथ में

सी. ए. संख्या 4217-4218 & 4219/2007

के. परासरन, आर. बालासुब्रमण्यम, अंभोज कुमार सिंह, ऐश्वर्या सिंह, सेंथिल जगदीशन, श्रुति लायर कंचना, उपस्थित पक्षकारों की ओर से।

न्यायालय का निर्णय एम. वाई. इकबाल, न्यायाधिपति. द्वारा दिया गया

1. ये अपीलें ए.एस. संख्या 665 और 666/2001 में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित सामान्य निर्णय और आदेश दिनांक 30.4.2004 के खिलाफ निर्देशित हैं, जिसके तहत एस.नटराजन द्वारा दायर अपीलों को स्वीकार किया गया। यह मामला क्रमांक 159/10 और 11, प्लॉट नंबर 436, तल्लाकुलम गांव, मदुरै शहर की संपत्ति से संबंधित है, जिसकी माप 6980 वर्ग फुट है। जिसे हाउसिंग बोर्ड द्वारा लीज-कम-सेल एग्रीमेंट पर एस. नटराजन को आवंटित किया गया था। एस नटराजन, ओएस नंबर 445/85 और 252/86 में मूल प्रतिवादी और ओएस नंबर 3/86 में वादी ने आरोप लगाया कि उसने एक इनबेसेगरन के साथ वाद संपत्ति के संबंध में बिक्री समझौता किया है।

इसलिए, सुविधा के लिए एस.नटराजन और इनबेसगरन को इसके बाद क्रमशः 'प्रतिवादी' और 'वादी' के रूप में संदर्भित किया जाता है।

2. वर्तमान अपीलों को जन्म देने वाले तथ्य यह हैं कि वादी ने उपरोक्त वाद अनुसूची संपत्ति के संबंध में दिनांक 19.1.1984 के बिक्री समझौते के विशिष्ट अनुपालना के लिए ओएस नंबर 252/1986 के तहत एक वाद दायर किया था। उनके अनुसार, तमिलनाडु आवास बोर्ड (संक्षेप में, 'आवास बोर्ड') द्वारा 4.7.1975 पर पट्टा-सह-बिक्री समझौते पर प्रतिवादी को उक्त भूमि आवंटित की गई थी। चूँकि प्रतिवादी ने पट्टा-सह-बिक्री समझौते के तहत विचार किए गए बिक्री विलेख प्राप्त करने के उद्देश्य से उक्त स्थल पर भवन का निर्माण नहीं किया था, इसलिए बोर्ड ने प्रतिवादी के पक्ष में बिक्री विलेख को निष्पादित नहीं किया। इसलिए, उन्होंने वादी के साथ 19.1.1984 पर एक बिक्री समझौता किया। उक्त समझौते में, वह वादी को वाद घर की साइट कुल 3,84,220/- रुपये प्रतिफल में बेचने के लिए सहमत हुआ और बिक्री प्रतिफल के हिस्से के रूप में नकद में 1,00,000/- रुपये की अग्रिम राशि प्राप्त की। यह आरोप लगाया जाता है कि प्रतिवादी इस बात पर सहमत हुआ कि आवास बोर्ड से उसके पक्ष में निष्पादित बिक्री विलेख के बाद वह शेष बिक्री पर विचार प्राप्त करने के बाद वादी या उसके परिवार के सदस्यों के पक्ष में बिक्री विलेख को निष्पादित और पंजीकृत करेगा। समझौते के निष्पादन के लिए समय अस्थायी रूप से चार महीने के रूप में अनुसूची किया गया था और इसे तब तक बढ़ाया गया था जब तक कि प्रतिवादी आवास बोर्ड से बिक्री विलेख निष्पादित नहीं कर लेता। पक्षकार इस बात पर सहमत हुए कि वादी उक्त संपत्ति में एक भवन के निर्माण के लिए एक योजना तैयार करेगा और प्रतिवादी भवन योजना पर हस्ताक्षर करेगा और योजना को मंजूरी दिलाएगा और उसके बाद वादी अपने खर्च पर वाद घर भूखंड में भवन का निर्माण करेगा।

3. बिक्री समझौते के अनुसार, वादी ने मुकदमे की संपत्ति पर कब्जा कर लिया और निर्माण पूरा कर लिया। वादी के अनुसार, प्रतिवादी वादी का प्रतिनिधित्व कर रहा था कि उसने अभी तक आवास बोर्ड से अपने पक्ष में बिक्री विलेख निष्पादित नहीं कराया है, लेकिन वादी द्वारा मुकदमा संपत्ति पर निर्मित इमारत पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया है। इसलिए वादी ने प्रतिवादी को मुकदमे की संपत्ति में निर्मित इमारत पर जबरन कब्जा करने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा के लिए 11.9.1985 पर ओ.एस. संख्या 445/1985 वाद दायर किया। उपरोक्त वाद के लंबित रहते हुए, कुछ दिनों बाद, 25.4.1986 को वादी ने ओ.एस. संख्या 252/1986 विशिष्ट अनुपालना के लिए उपरोक्त वाद दायर किया।

4. प्रतिवादी ने अपने लिखित बयान में दलील दी कि 19.1.1984 दिनांकित समझौता एक वैध दस्तावेज नहीं है और वादी मुकदमे को बनाए नहीं रख सकता क्योंकि उसने अपना अधिकार छोड़ दिया था। यह भी कहा गया है कि समझौते का निष्पादन तब किया गया था जब प्रतिवादी साइट का मालिक नहीं था और प्रतिवादी द्वारा किसी भी बिक्री को आवास बोर्ड के साथ किए गए पट्टा-सह-बिक्री समझौते के नियमों और शर्तों के अनुसार प्रतिबंधित किया गया था और इसलिए विचाराधीन समझौता अमान्य, निष्क्रिय और कानून के खिलाफ है। प्रतिवादी ने अग्रिम के रूप में नकद 1,00,000/- रुपये के भुगतान से भी इनकार कर दिया, जैसा कि वादी ने आरोप लगाया था। यहां तक कि वादपत्र में दिए गए इस कथन के संबंध में भी कि वादी को वाद स्थल पर निर्माण करने की अनुमति दी गई थी, इसे अस्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी ने इस बात से भी इनकार किया कि वादी ने अपनी कीमत पर निर्माण किया था। प्रतिवादी ने आगे इस बात से इनकार किया कि वादी को वाद संपत्ति का कब्जा दिया गया था और दावा किया कि उसने कभी भी किसी भी समय वादी को संपत्ति का कब्जा नहीं सौंपा। यह आरोप लगाया जाता है कि वादी विशिष्ट अनुपालना के लिए डिक्री

का हकदार नहीं है क्योंकि 19.1.1984 दिनांकित समझौता अब अस्तित्व में नहीं है। यह आगे आरोप लगाया जाता है कि विशिष्ट अनुपालना के लिए ओ.एस.संख्या 252/1986 होने के बाद का वाद सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 2, नियम 2 के तहत वर्जित है क्योंकि वादी जिसने पहले ओ.एस. संख्या 445/1985 का वाद दायर किया था, उसे विशिष्ट अनुपालना के लिए राहत शामिल करनी चाहिए थी और किसी भी स्थिति में, न्यायालय की अनुमति के बिना ओ.एस. संख्या 252/1986 दायर नहीं कर सकता था।

5. प्रतिवादी ने एक वाद ओ.एस. संख्या 3/1986 भी दायर किया जिसमें खरीददार (उसमें प्रतिवादी) को मुकदमे की संपत्ति के कब्जे और आनंद में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा के लिए एक डिक्री की मांग की गई। विचारण न्यायालय ने तीनों मुकदमों की एक साथ सुनवाई की और ओ.एस. संख्या 445/1985 और 3/1986 में निषेधाज्ञा के लिए वादी और प्रतिवादी द्वारा दायर मुकदमों को खारिज कर दिया और प्रतिवादी को वादी के पक्ष में बिक्री दस्तावेज को निष्पादित करने और पंजीकृत करने के निर्देश के साथ विशिष्ट अनुपालना के लिए वादी द्वारा दायर किए गए ओ.एस. संख्या 252/1986 में वाद का फैसला सुनाया।

6. विचारण न्यायालय के फैसले और डिक्री से व्यथित, प्रतिवादी एस. नटराजन ने ए.एस. संख्या 665 और 666/2001 के रूप में उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की।

7. उच्च न्यायालय ने कहा कि अपीलकर्ता द्वारा दायर दोनों मुकदमों में वाद हेतुक समान हैं, एक ही लेन-देन से उत्पन्न हुए हैं और यही कारण है कि विचारण न्यायालय ने भी एक सामान्य परीक्षण किया और एक सामान्य निर्णय द्वारा मामले का फैसला किया। वादी ओ.एस. 252/1986 में इस तथ्य के आधार पर वाद के साथ आगे नहीं आया है कि वाद संपत्ति के संबंध में बिक्री विलेख केवल आवास बोर्ड से प्रतिवादी द्वारा 18.2.1985 पर प्राप्त किया गया था और प्रतिवादी प्रदर्श ए1 समझौते के अनुसार

वादी के पक्ष में बिक्री विलेख को निष्पादित करने में विफल रहा और इसलिए उक्त मुकदमे में मांगी गई प्रार्थना मूल वाद संख्या 445/1985 में भी मांगी जा सकती थी क्योंकि ओ.एस. 252/1986 में शिकायत में निर्धारित अभिवचन उस तारीख को भी उपलब्ध था जब ओ.एस. संख्या 445/1985 दायर किया गया था। चूँकि वादी ने इस तरह की राहत लेने में चूक की और बाद का वाद दायर करने के लिए विचारण न्यायालय की अनुमति प्राप्त नहीं की, इसलिए यह उसके अधिकारों का त्याग करने के बराबर है जो ओ.एस. 252/1986 में मांगा गया है और वह संहिता के आदेश 2, नियम 2 को देखते हुए उस वाद में मांगी गई राहत के लिए ओ.एस. 252/1986 में बाद के वाद को कायम नहीं रख सकता है।

8. उच्च न्यायालय ने अपीलों पर निर्णय लेने के लिए विचार के लिए निम्नलिखित छह बिंदु तैयार किएः

(1) क्या प्रदर्श ए1 कानून द्वारा प्रवर्तनीय है?

(2) क्या वाद ओ.एस. संख्या 252/1986 प्रदर्श बी7 और बी9 में किये गए बदलाव को देखते हुए प्रदर्श ए1 के आधार पर बनाए रखने योग्य है?

(3) क्या प्रत्यर्थी/वादी करार के अपने हिस्से को पूरा करने के लिए तैयार और इच्छुक था?

(4) क्या वाद ओ.एस. 252/1986 सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 2, नियम 2 को देखते हुए बनाए रखने योग्य है?

(5) क्या समझौता वाद ओ.एस. 252/1986 में विशिष्ट अनुपालना की राहत को इस आधार पर खारिज किया जा सकता है कि प्रत्यर्थी/ वादी न्यायालय में स्वच्छ हाथों से नहीं आया है?

9. हालाँकि, सभी बिंदुओं पर निर्णय लेने के बजाय, उच्च न्यायालय ने केवल बिंदु संख्या 4 और 5 पर विचार किया और निम्नलिखित तीन पैराग्राफ में अपील का फैसला कियाः

> "13. इसके अलावा, वर्तमान मामले में, पक्षों और न्यायालय ने महसूस किया कि सामान्य मुद्दे को देखते हुए, उक्त वाद से निपटा जाना था और इसलिए विचारण न्यायालय ने दिनांक 28.7.2000 के एक सामान्य फैसले में इसका निस्तारण कर दिया। विचारण न्यायालय ने हालांकि इस मुद्दे को तैयार किया, लेकिन केवल इस बात को खारिज कर दिया कि यह संहिता के आदेश 2, नियम 2 द्वारा इस धारणा पर वर्जित नहीं है कि वाद हेतुक में बदलाव हुआ है। इसलिए विचारण न्यायालय के उक्त निष्कर्षों को कानूनी रूप से कायम नहीं रखा जा सकता है। इसलिए हम सुरक्षित रूप से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ओ.एस.सं.252/1986 में वाद संहिता के आदेश 2, नियम 2 के तहत वर्जित है और इसलिए इसे खारिज करना होगा।
>
> 14. यहां तक कि बिंदु संख्या 5 के संबंध में, यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि प्रत्यर्थी/वादी ओ.एस. 252/1986 अशुद्ध हाथों से दायर करके न्यायालय में आया है। यद्यपि ओ.एस. संख्या 3/1986 में दायर शिकायत में जो 5.9.1985 को दायर की गई थी, यह विशेष रूप से कहा गया है कि तमिलनाडु आवास बोर्ड द्वारा अपीलार्थी/प्रतिवादी के पक्ष में दिनांकित 18.2.1985 सशर्त बिक्री विलेख निष्पादित किया गया था। ओ.एस. No.252/1986 में, जो 5.4.1986 को दायर किया गया था, प्रत्यर्थी/वादी इस झूठी याचिका के साथ आगे आया है कि अपीलार्थी/प्रतिवादी वादी का प्रतिनिधित्व

कर रहा था कि उसने अभी तक तमिलनाडु आवास बोर्ड द्वारा अपने पक्ष में बिक्री विलेख निष्पादित नहीं कराया था, जो पहले के वाद में किए गए कथन के विपरीत है। प्रत्यर्थी/वादी के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत करने की कोशिश की कि प्रत्यर्थी को उक्त दस्तावेज़ के बारे में कोई जानकारी नहीं है ताकि वह उस आधार पर समझौते के विशिष्ट अनुपालना के लिए वाद दायर कर सके। ओ.एस. संख्या 3/1986 में वाद में किए गए विशिष्ट कथन को देखते हुए उक्त याचिका और कुछ नहीं बल्कि झूठी है। उक्त याचिका कि अपीलार्थी/प्रतिवादी द्वारा तमिलनाडु आवास बोर्ड से बिक्री विलेख अभी तक प्राप्त नहीं किया गया है, अधिकार को लागू करने के लिए एक भौतिक तथ्य है और प्रतिवादी/वादी द्वारा बिक्री विलेख तमिलनाडु आवास बोर्ड से अपीलार्थी/प्रतिवादी द्वारा बिक्री विलेख प्राप्त करने के बाद ही उत्पन्न हुआ जैसा कि प्रदर्श ए1 के तहत विचार किया गया है। प्रत्यर्थी/वादी ने उक्त भौतिक तथ्य को दबा दिया। इसलिए, उस आधार पर भी ओ.एस. 252/1986 में वाद को यह मानते हुए खारिज किया जाना चाहिए कि प्रतिवादी/वादी उपरोक्त तथ्य को देखते हुए समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन की न्यायसंगत राहत का हकदार नहीं है।

15. बिंदु संख्या 4 और 5 के संबंध में ऊपर दिए गए निष्कर्षों को देखते हुए, हम अन्य बिंदुओं से निपटने के लिए इच्छुक नहीं हैं।"

10. दिनांक 30.4.2004 के आक्षेपित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने आदेश 2 नियम 2 के आधार पर प्रतिवादी द्वारा की गई अपीलों को स्वीकार किया, जिसमें प्रतिवादी को निर्माण की लागत (रु. 8,00,000-) का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था और इस तरह की जमा राशि पर, वादी प्रतिवादी को भवन के साथ मुकदमा

संपत्ति सौंप देगा और उसे सौंपने के बाद, वह पहले से जमा की गई राशि, यदि कोई हो, के साथ उपरोक्त राशि को निकाल सकता है। इसलिए, दोनों पक्षों द्वारा परस्पर अपील प्रस्तुत की जाती है। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि किसी अन्य मुद्दे पर विचार करने और निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है।

11. अपीलार्थी-वादी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के.परासरन ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय फैसले को कानून के साथ-साथ तथ्यों में भी गलत बताया। विद्वान अधिवक्ता ने सबसे पहले दिनांकित 19.1.1984 को बेचने के समझौते की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया और प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी-प्रतिवादी ने उक्त समझौते में एक शर्त रखी है कि बिक्री विलेख का निष्पादन प्रतिवादी द्वारा वादी के पक्ष में आवास बोर्ड द्वारा पट्टे पर रखे गए भूखंड का हस्तांतरण प्राप्त करने के बाद ही किया जाएगा। हालांकि, प्रत्यर्थी-प्रतिवादी के पक्ष में आवास बोर्ड द्वारा संपत्ति के हस्तांतरण के लंबित रहने तक, प्रतिवादी के उपद्रवी तत्वों ने अपीलकर्ता-वादी को वादी द्वारा निर्मित भवन से बेदखल करने की धमकी दी। प्रतिवादी को प्रतिबंधित और रोकने के लिए, अपीलार्थी ने 1985 के ओ.एस. संख्या 445 के रूप में निषेधाज्ञा के लिए एक वाद दायर किया, जिसमें प्रतिवादी को वादी को बेदखल करने से रोकने वाले निषेधात्मक आदेश की मांग की गई।

12. साथ ही, विचारण न्यायालय के समक्ष, प्रत्यर्थी-प्रतिवादी ने भी ओ.एस. संख्या 3/1986 (13/1985) के रूप में एक वाद दायर किया, जिसमें अपीलार्थी के खिलाफ निषेधाज्ञा के लिए इसी तरह का अनुरोध किया गया था। उक्त वाद के लिखित कथन में, पहली बार वाद के प्रतिवादी (यहाँ अपीलकर्ता) ने पैराग्राफ 4 में खुलासा किया कि बिक्री विलेख आवास बोर्ड द्वारा उसके पक्ष में निष्पादित किया गया था और अब वाद का वादी (यहाँ प्रतिवादी) संपत्ति का पूर्ण स्वामी है। आवास बोर्ड द्वारा वादी के पक्ष में संपत्ति के हस्तांतरण के बारे में जानने के बाद, अपीलार्थी द्वारा प्रतिवादी को कानूनी

नोटिस दिए गए और विशिष्ट अनुपालना के लिए एक नियमित मुकदमा वाद किया गया।

13. श्री परासरन ने प्रस्तुत किया कि दो वादों में वादपत्रों को पढ़ने से, यह प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट होगा कि वादी द्वारा दोनों वादों में से प्रत्येक की वाद हेतुक काफी अलग और विशिष्ट थी और यह आदेश 2, नियम 2 सी. पी. सी. के प्रावधानों को आकर्षित नहीं करेगा। श्री परासरन ने आगे कहा कि विचारण न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा था कि आदेश 2, नियम 2 के प्रावधान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में लागू नहीं होंगे। श्री परासरन ने तब हमारा ध्यान दिनांकित 19.1.1984 के समझौते और दिनांकित 31.4.1984 कोडिसिल बिक्री समझौते की ओर आकर्षित किया ताकि यह दिखाया जा सके कि वादी-अपीलार्थी और प्रत्यर्थी-प्रतिवादी के बीच बिक्री समझौते की अवधि को प्रतिवादी के पक्ष में आवास बोर्ड द्वारा संपत्ति के हस्तांतरण की प्रत्याशा में और बढ़ा दिया गया था। अंत में, यह तर्क दिया गया कि आदेश 2 नियम 2, सी. पी. सी. का प्रावधान लागू नहीं होता है जहां दो वाद कार्रवाई के अलग-अलग कारणों पर दायर किए जाते हैं और अधिवक्ता ने गुरबक्स सिंह बनाम भुरालाल, (1964) 7 एस. सी. आर. 831; केवल सिंह बनाम लाजवंती, (1980) 1 एस. सी. सी. 290 और लक्ष्मी उपनाम भाग्यलक्ष्मी और एक अन्य बनाम ई. जयराम (मृत) के मामले में एल. आर., (2013) 9 एस. सी. सी. 311 के मामलों में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया।

14. प्रत्यर्थी-प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर. बालासुब्रमण्यम ने सबसे पहले प्रस्तुत किया कि यदि वादी-अपीलकर्ता द्वारा दायर मुकदमा में लगाए गए आरोपों को एक साथ पढ़ा जाए तो यह स्पष्ट होगा कि वादी को प्रतिवादी के पक्ष में आवास बोर्ड द्वारा निष्पादित बिक्री विलेख के बारे में जानकारी थी। यह केवल इसलिए था कि वाद में वादी ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह विशिष्ट अनुपालना के लिए वाद दायर करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखता है। विद्वान अधिवक्ता के

अनुसार, वादी द्वारा दायर दोनों वादों में वाद हेतुक समान हैं, इसलिए, विशिष्ट अनुपालना के लिए बाद का मुकदमा आदेश 2 नियम 2 सी. पी. सी. के तहत वर्जित होने के कारण बनाए रखने योग्य नहीं है। विद्वान अधिवक्ता विर्गो इंडस्ट्रीज (इंजीनियरिंग) (पी) लिमिटेड बनाम वेंचरटेक सॉल्यूशंस (पी) लिमिटेड, (2013) 1 एससीसी 625 के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर बहुत अधिक भरोसा रखते हैं।

15. हमने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना, विचारण न्यायालय और प्रथम अपील न्यायालय द्वारा दर्ज की गई दलीलों और निष्कर्षों का अध्ययन किया है।

16. सुनिश्चित रूप से, प्रथम वाद ओ.एस. संख्या 445/1985, जो वादी-अपीलार्थी द्वारा प्रतिवादी, उसके एजेंटों और सेवकों को वादी द्वारा वाद की संपत्ति के कब्जे और आनंद में इसमें या किसी अन्य तरीके से अतिक्रमण करने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा देने के लिए दायर किया गया था। अन्य तथ्यों के अलावा, यह दलील दी गई कि बिक्री समझौते के अनुसरण में वादी ने प्रतिवादी से वाद की साजिश कर भूखंड पर कब्जा कर लिया और कल्याण महल का निर्माण शुरू कर दिया। वादी द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि प्रतिवादी एक दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य और अधिक धन निकालने के इरादे से वादी का प्रतिनिधित्व कर रहा था कि वह आवास बोर्ड से बिक्री विलेख प्राप्त करने के बाद और भवन का निर्माण पूरा होने के बाद बिक्री विलेख को निष्पादित करेगा। उस गुप्त उद्देश्य के साथ, प्रतिवादी ने वादी द्वारा निर्मित इमारत पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की और वादी के कर्मचारी को उन्हें इमारत से हटाने की धमकी दी। वादी ने तब पुलिस को शिकायत दी और जवाब में, पुलिस तुरंत वाद संपत्ति में गई और उपद्रवियों को इमारत में प्रवेश नहीं करने की चेतावनी दी। इसलिए, वादी ने दलील दी कि प्रतिवादी फिर से अनियंत्रित तत्वों को इकट्ठा करने और वादी से वाद की संपत्ति को जबरन और गैरकानूनी रूप से कब्जे में लेने की व्यवस्था कर रहा था।

उस आशंका के साथ, मुकदमा मुख्य रूप से कार्रवाई के कारण पर दायर किया गया था जो तब उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी ने वादी के श्रमिकों को भगाकर मुकदमे की संपत्ति पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया और प्रतिवादी जबरन और गैरकानूनी तरीके से मुकदमे की संपत्ति पर कब्जा करने की व्यवस्था कर रहा था। प्रतिवादी ने अपने लिखित बयान में प्रत्येक आरोप से इनकार किया और कहा कि इमारत का निर्माण उसके द्वारा किया गया था और वास्तव में वादी ने जबरन इमारत पर कब्जा करने का प्रयास किया था।

17. वादी द्वारा ओ.एस. संख्या 252/1986 में दायर किए गए बाद के मुकदमे में, समझौते के विशिष्ट अनुपालना के लिए एक डिक्री का दावा इस आधार पर किया गया था कि पहले के वाद में प्रतिवादी ने बचाव किया था कि बिक्री समझौते को कथित तौर पर छोड़ दिया गया था या हटा दिया गया था। वाद हेतुक, जैसा कि बाद के वाद ने अन्य बातों के साथ साथ वादी द्वारा अनुरोध किया गया था, तब उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी-प्रतिवादी ने अपने पक्ष अन्य बातों के साथ साथ आवास बोर्ड द्वारा किए गए हस्तांतरण का खुलासा किया और अंततः अन्य बातों के साथ साथ जब प्रतिवादी बिक्री समझौते के अपने हिस्से का अनुपालन नहीं करने का इरादा दिखा रहा था और अधिवक्ता के नोटिस के जवाब अन्य बातों के साथ साथ प्रतिवादी ने झूठा आरोप लगाया और समझौते के अनुसार बिक्री विलेख को निष्पादित करने से इनकार कर दिया।

18. दोनों वादों में दलीलों और उसमें उल्लिखित वाद हेतुक के अवलोकन से पता चलेगा कि वाद हेतुक और मांगी गई राहतें बिलकुल अलग है और समान नहीं है।

19. निर्विवाद रूप से, वाद हेतुक में तथ्यों का एक समूह होता है जो वादी के लिए न्यायालय से राहत प्राप्त करने के लिए साबित करने के लिए आवश्यक होगा। हालाँकि, क्योंकि दोनों वादों के लिए वाद हेतुक अलग-अलग और विशिष्ट हैं और दोनों

वादों में राहत का समर्थन करने के लिए सबूत भी अलग-अलग हैं, तो आदेश 2 नियम 2 सी. पी. सी. के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

20. मोहम्मद खलील खान बनाम अन्य अन्य महबूब अली मियां बनाम अन्य, ए. आई. आर. (36) 1949 प्रिवी काउंसिल 78 के मामले में प्रिवी काउंसिल द्वारा इस प्रावधान पर अच्छी तरह से चर्चा की गई है, निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया: -

> "61 अब तक जिन मामलों पर चर्चा की गई है, उनमें निर्धारित सिद्धांतों का सारांश इस प्रकार दिया जा सकता है:-
>
> (1) आदेश 2, नियम 2 के तहत आने वाले मामलों में सही परीक्षण यह है कि "क्या नए वाद में दावा वास्तव में उस वाद हेतुक पर आधारित है जो पहले के वाद की नींव थी।" मूनशी बुजलूर रुहीम बनाम शमसुन्निसा बेगम (1867-11) एम.आई.ए. 551.
>
> (2) वाद हेतुक का अर्थ है हर वह तथ्य जो वादी के लिए साबित करने के लिए आवश्यक होगा यदि उसे निर्णय के अपने अधिकार का समर्थन करने के लिए किया गया है। रीड बनाम ब्राउन (1889-22) क्यू.बी.पी. 128।
>
> (3) यदि दोनों दावों का समर्थन करने वाले साक्ष्य अलग-अलग हैं, तो वाद हेतुक भी अलग-अलग हैं। ब्रन्सडेन बनाम हम्फ्री (1884-14) क्यू.बी.डी. 141.
>
> (4) दोनों मुकदमों में वाद हेतुक को समान माना जा सकता है यदि वे सार में समान हैं। ब्रन्सडेन बनाम हम्फ्री (1884-14) क्यू.बी.डी. 141.

(5) वाद हेतुक का प्रतिवादी द्वारा स्थापित किए गए बचाव से कोई संबंध नहीं है और न ही यह वादी द्वारा मांगी गई राहत के चरित्र पर निर्भर करता है। यह मीडिया को इंगित करता है जिस पर वादी न्यायालय से अपने पक्ष में एक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कहता है। मुस. चांद कौर बनाम प्रताप सिंह (15 आई.ए. 156: केल.98 पी.सी.)। यह अवलोकन लॉर्ट वॉटसन द्वारा 1882 के अधिनियम की धारा 43 (आदेश 2, नियम 2 के अनुरूप) के तहत एक मामले में किया गया था, जहां वादी ने एक ही वाद में विभिन्न दावे किए थे।"

21. इस न्यायालय की संविधान पीठ ने सी.पी.सी. के आदेश 2 नियम 2 के दायरे और प्रयोज्यता पर विचार करते हुए, गुरबक्स सिंह बनाम भुरालाल, (ऊपर) एआईआर 1964 एससी 1810 के मामले में निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

"6. सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 2 नियम 2 (3) के तहत वर्जित होने की याचिका सफल होने चाहिए, जो प्रतिवादी याचिका उठाता है, उसे यह बताना चाहिए कि (i) कि दूसरा वाद उसी वाद हेतुक के संबंध में था जिस पर पिछला वाद आधारित था; (2) वाद हेतुक के संबंध में वादी एक से अधिक राहत का हकदार था; (3) इस प्रकार एक से अधिक राहत का हकदार होने के कारण वादी को न्यायालय से प्राप्त अनुमति के बिना उस राहत के लिए वाद करने से हटा दिया गया, जिसके लिए दूसरा वाद दायर किया गया था। इस विश्लेषण से यह देखा जाएगा कि प्रतिवादी को मुख्य रूप से और शुरुआत में कार्रवाई के सटीक कारण को स्थापित करना होगा, जिस पर पिछला वाद दायर किया गया था, जब तक कि वाद हेतुक के बीच पहचान न हो, जिस पर पहले का वाद दायर किया गया था और जिस पर बाद

के वाद में दावा आधारित है, तब तक वर्जित होने के आवेदन की कोई गुंजाइश नहीं होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मुकदमा में मांगी गई राहत आमतौर पर कार्रवाई के किसी विशेष कारण के लिए पता लगाने योग्य हो सकती है, लेकिन यह किसी भी तरह से सार्वभौमिक नियम नहीं हो सकता है। चूंकि याचिका एक तकनीकी बाधा है, इसलिए इसे संतोषजनक रूप से स्थापित किया जाना चाहिए और इसे केवल अनुमानित तर्क के आधार पर नहीं माना जा सकता है। यही कारण है कि हम मानते हैं कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 2 नियम 2 के तहत वर्जित होने की याचिका केवल तभी स्थापित की जा सकती है जब प्रतिवादी पिछले वाद में दलीलें साक्ष्य में दाखिल करता है और इस तरह न्यायालय को दोनों वादों में वाद हेतुक की पहचान साबित करता है। यह सामान्य आधार है कि सी.एस.28/1950 में अभिवचन वर्तमान वाद में अपीलकर्ता द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 2 नियम 2 के तहत अपनी याचिका के समर्थन में साक्ष्य के रूप में दायर नहीं किए गए थे। हालाँकि, विद्वत विचारण न्यायालय ने इन अभिवचनों को अभिलेख में रखे बिना अनुमान लगाया कि कटौती के मामले के रूप में वाद में निहित पिछले वाद के संदर्भ से वाद हेतुक क्या होना चाहिए था। अपील के चरण में विद्वान जिला न्यायाधीश ने अपीलार्थी के मामले में इस कमी को देखा और हमारी राय में सही बताया कि पिछले वाद में शिकायत के रिकॉर्ड में होने के बिना, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 2 नियम 2 के तहत एक बार की याचिका बनाए रखने योग्य नहीं थी।

XXXXX

यह उनका निवेदन था कि इस परिच्छेद से हमें यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि पक्षों ने सहमती से, पिछले वाद की दलीलों को वर्तमान वाद में रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने पर सहमती व्यक्त की थी। हम इन टिप्पणियों की इस व्याख्या से सहमत होने में असमर्थ हैं। "हालांकि, दोनों न्यायालयों ने पहले के वाद के रिकॉर्ड का स्वतंत्र रूप से हवाला दिया है" स्पष्ट रूप से गलत है क्योंकि विद्वान जिला न्यायाधीश ने विशेष रूप से इंगित किया है कि पहले के वाद में दलीलें रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं थीं और उसी आधार पर सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 2 नियम 2 के तहत बार की याचिका को खारिज कर दिया था। न ही हमें इस सुझाव का कोई आधार मिल सकता है कि विद्वान न्यायाधीश ने पक्षकारों की सहमति से सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 27 के तहत दूसरे अपील चरण में इन दस्तावेजों को स्वीकार कर लिया था। इस तरह के समझौते या ऐसे आदेश का सुझाव देने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है, यह मानते हुए कि अतिरिक्त साक्ष्य को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 27 के तहत दूसरी अपील में वैध रूप से स्वीकार किया जा सकता है। इसलिए हम केवल इस आधार पर आगे बढ़ सकते हैं कि पिछले वाद की दलीलें वर्तमान वाद के रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं थीं।"

22. केवल सिंह बनाम लाजवंती (ऊपर) के मामले में, आदेश 2 नियम 2 सी. पी. सी. की प्रयोज्यता पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने कहा किः -

"5. जहाँ तक पहली दो दलीलों का संबंध है, हमारी राय है कि वे किसी भी गंभीर विचार के योग्य नहीं हैं। आदेश 2 नियम 2 सी.पी.सी. की प्रयोज्यता के प्रश्न के संबंध में अपीलकर्ता के विद्वान

अधिवक्ता का तर्क कानून की गंभीर गलत धारणा पर आधारित है। आदेश 2 नियम 2 सी. पी. सी. इस प्रकार चलता हैः

> "2(1) हर वाद के अंतर्गत वह पूरा दावा होगा जिसे उस वाद हेतुक के विषय में करने का वादी हक़दार है, किन्तु वादी वाद को किसी न्यायालय की अधिकारिता के भीतर लेन की द्रष्टि से अपने दावे के किसी भाग का त्याग कर सकेगा ।
>
> (2) जहां वादी अपने दावे के किसी भाग के बारे में वाद लेन का लोप करता है या उसे साशय त्याग देता है वहां उसके पश्चात वह इस प्रकार लोप किये गए या त्यक्त भाग के बारे में वाद नहीं लायेगा।"

आदेश 2 नियम 2 के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि यह प्रावधान उन मामलों में लागू होता है जहां कोई वादी वाद हेतुक एक हिस्से पर वाद करने से चूक जाता है, जिस पर वाद या तो वाद हेतुक को छोड़कर या उसके एक हिस्से को छोड़कर आधारित है। इसलिए, यह प्रावधान उन मामलों में लागू नहीं होता है जहां वादी अपने वाद को वाद हेतुक और विशिष्ट कारणों पर आधारित करता है और उनमें से एक या दूसरे को छोड़ने का विकल्प चुनता है। ऐसे मामलों में, वादी के लिए यह हमेशा खुला रहता है कि वह वाद के एक विशिष्ट हेतुक के आधार पर एक नया वाद दायर करे जिसे उसने त्याग दिया होगा।

6. मोहम्मद खलील खान बनाम महबूब अली मियां, एआईआर 1949 पीसी 78 के मामले में, प्रिवी काउंसिल ने निम्नानुसार टिप्पणी कीः

"यह कि अधिकार और उसका उल्लंघन, न कि अधिकार का और उसके उल्लंघन का आधार या उत्पत्ति, वाद हेतुक बनते है, बल्कि जहां तक महबूब भाइयों का संबंध है, अवध मुकदमे (8/1928) के लिए वाद हेतुक केवल उनके द्वारा स्वामित्व से इनकार था क्योंकि वह मुकदमा मुख्य रूप से अबादी बेगम के खिलाफ अवध संपत्ति के कब्जे के लिए था; जबकि वर्तमान वाद में वाद हेतुक शाहजहांपुर संपत्ति के महबूब भाइयों द्वारा गलत कब्जा था, और यह कि कार्रवाई के दो कारण इस प्रकार अलग थे।

7. प्रिवी काउंसिल द्वारा निर्धारित उपरोक्त सिद्धांतों को लागू करते हुए हम पाते हैं कि प्रिवी काउंसिल द्वारा उल्लिखित शर्तों में से कोई भी इस मामले में लागू नहीं होती है। वादी ने पहले अपना वाद कार्रवाई के तीन अलग-अलग कारणों पर आधारित किया था, लेकिन बाद में वाद को केवल कार्रवाई के पहले कारण तक सीमित कर दिया, जिसका उल्लेख अधिनियम की धारा 14-ए(1) में किया गया था और धारा 14(1)(ई) और (एफ) से संबंधित वाद हेतुक को छोड़ दिया। इसके बाद, एक संशोधन के आधार पर उन्होंने धारा 14-ए(1) से उत्पन्न कार्रवाई के पहले कारण को छोड़ दिया और धारा 14(1)(ई) के आधार पर वाद हेतुक को पुनर्जीवित करने की मांग की। जिस समय वादी ने धारा 14(1)(ई) से उत्पन्न वाद हेतुक छोड़ दिया था, उस समय प्रतिवादी तस्वीर में बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए, वादी द्वारा मांगे गए संशोधन पर कोई आपत्ति उठाने के लिए प्रतिवादी खुला नहीं था। इन कारणों से, हम संतुष्ट हैं कि दूसरा संशोधन आवेदन आदेश 2

नियम 2 सी. पी. सी. के सिद्धांतों द्वारा बाधित नहीं था और अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क विफल होना चाहिए।"

23. देवा राम बनाम ईश्वर चंद, (1995) 6 एससीसी 733 के मामले में, इस न्यायालय ने अपने पहले के विभिन्न निर्णयों पर विचार करते हुए निम्नलिखित टिप्पणी कीः -

"14. इसलिए, नियम के लिए एक वाद में वाद हेतुक एक ही कारण के आधार पर सभी दावों की एकता की आवश्यकता है। यह कार्य के विशिष्ट और अलग-अलग कारणों की एकता पर विचार नहीं करता है। यदि, इसलिए, बाद का वाद एक अलग कारण पर आधारित है, तो नियम एक प्रतिबंध के रूप में काम नहीं करेगा। (देखें अर्जुन लाल गुप्ता बनाम मृगांका मोहन सूर, (1974) 2 एससीसी 586; एम.पी. राज्य बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1977) 2 एससीसी 288; केवल सिंह बनाम बी. लाजवंती, (1980) 1 एससीसी 290)।

15. सिद्रमप्पा बनाम राजशेट्टी, (1970) 1 एससीसी 186 में, यह निर्धारित किया गया था कि यदि वाद हेतुक जिसके आधार पर पिछला वाद लाया गया था, बाद के वाद का आधार नहीं बनता है और पहले के वाद में वादी उस राहत का दावा नहीं कर सकता था जो उसने बाद के वाद में मांगी थी, तो बाद वाला, बाद का मुकदमा, आदेश 2 नियम 2, सी.पी.सी. में निहित नियम द्वारा बाधित नहीं किया जाएगा।

24. सिद्रमप्पा बनाम राजशेट्टी और अन्य, ए. आई. आर. (1970) एस. सी. 1059 के मामले में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

"7. उच्च न्यायालय और विचारण न्यायालय ने गलत आधार पर कार्यवाही की कि पूर्व वाद वादी की अनुसूची । में उल्लिखित भूमि पर

वादी के स्वामित्व की घोषणा के लिए एक वाद था। आदेश ॥ नियम 2, सिविल प्रक्रिया संहिता की आवश्यकता यह है कि प्रत्येक वाद में वह पूरा दावा शामिल होना चाहिए जो वादी वाद हेतुक के संबंध में करने का हकदार है। "वाद हेतुक" का अर्थ है "कार्यवाही का वह कारण जिसके लिए वाद दायर किया गया था"। यह नहीं कहा जा सकता है कि जिस कार्रवाई पर वर्तमान वाद दायर किया गया था, उसका कारण वही है जो पिछले वाद में था। वाद हेतुक कार्रवाई का एक कारण है जो वाद करने के लिए अवसर देता है और इसकी नींव बनाता है। यदि ऐसा वाद हेतुक किसी व्यक्ति को अपने दावे को सीमित करने की तुलना में अधिक और व्यापक राहत की मांग करने में सक्षम बनाता है, तो वह बाद में स्वतंत्र कार्यवाही द्वारा संतुलन की वसूली नहीं कर सकता है। - देखें मोहम्मद हाफिज बनाम मोहम्मद जकारिया एआईआर (1922) पीसी 23"।

8. जैसा कि पहले देखा गया है कि वाद हेतुक जिसके आधार पर पिछला वाद लाया गया था, वर्तमान वाद का आधार नहीं बनाता है। पहले के वाद में उल्लिखित वाद हेतुक, यह मानते हुए कि यह एक वैध दावे के लिए एक आधार प्रदान करता है, वादी को उन लोगों के अलावा किसी भी राहत मांगने में सक्षम नहीं बनाता है, जिसके लिए उसने उस वाद में प्रार्थना की थी। उस वाद में वह उस राहत का दावा नहीं कर सकता था जो वह इस वाद में चाहता है। इसलिए विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय का यह मानना सही नहीं था कि वादी का वाद आदेश ॥, नियम 2, सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा वर्जित है।"

25. एम.पी. राज्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य, (1977) 2 एससीसी 288 के मामले में, पृष्ठ 295 पर इस न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी कीः -

> "24. बिहार राज्य बनाम अब्दुल माजिद, एआईआर 1954 एससी 245 में इस न्यायालय ने कहा कि एक सरकारी कर्मचारी वेतन बकाया की मांग कर सकता है। मध्य प्रदेश के अधिवक्ता ने कहा कि अब्दुल माजिद मामले में इस न्यायालय के फैसले ने घोषित किया कि मौजूदा कानून क्या है, और इसलिए, वादी यह तर्क नहीं दे सकता कि 1949 के मुकदमे में वेतन बकाया की मांग करने के लिए वह अधिकारी नहीं था। इसी पृष्ठभूमि में मध्य प्रदेश का तर्क है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 2 नियम 2 के तहत राहत नहीं मांगने वाला वादी 1956 के वाद में वेतन का दावा करने का हकदार नहीं होगा।
>
> 25. मध्य प्रदेश के तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। वादकारी को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 2 नियम 2 के तहत केवल तभी प्रतिबंधित किया जाएगा जब वह इस ज्ञान के साथ वाद में दावे को छोड़ देता है कि उसे उस राहत के लिए वाद करने का अधिकार है। यह कहना सही नहीं होगा कि जब लाल मामले में न्यायिक समिति का निर्णय प्रभावी था, तब वादी को यह बताया जा सकता था कि वह अभी भी वेतन के बकाया के लिए दावा करने का हकदार है। इसके विपरीत, यह कहना सही होगा कि वह जानता था कि वह ऐसा दावा करने का हकदार नहीं था। यदि पूर्व वाद की तिथि पर वादकारी को उस अधिकार के बारे में जानकारी नहीं है जिस पर वह बाद के वाद में जोर देता है तो वादकारी को बाद के वाद में राहत

का हकदार नहीं कहा जा सकता है। कारण यह है कि पूर्व वाद की तिथि पर वादकारी को उस अधिकार के बारे में जानकारी नहीं होती है जिस पर वह बाद के वाद में जोर देता है। एक अधिकार जिसे एक वादकारी नहीं जानता है कि उसके पास है या एक अधिकार जो पहले वाद के समय अस्तित्व में नहीं है, शायद ही सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 2 नियम 2 के अर्थ के भीतर "उसके दावे का एक हिस्सा" माना जा सकता है। देखें- अमानत बीबी बनाम इमदाद हुसैन, (1885) 15 इंड एपीपी 106 पृष्ठ 112(पीसी)। मामले की जड़ पहले वाद के समय अधिकार की उपस्थिति या जागरूकता की कमी है।

27. इसलिए, अपीलकर्ता मध्य प्रदेश का यह तर्क देना सही नहीं है कि वादी को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 2 नियम 2 में निहित प्रावधानों द्वारा 1956 के वाद में वेतन की बकाया राशि मांगने से रोक दिया गया है। वादी कानून के तहत वेतन बकाया की मांग नहीं कर सकता था जैसा कि तब था। वादी को इस तरह के किसी भी अधिकार के बारे में पता नहीं था या उसके पास नहीं था। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि वादी ने किसी भी अधिकार के लिए वाद करना छोड़ दिया है।"

26. चर्चा किए गए सिद्धांतों और संविधान पीठ द्वारा निर्धारित कानून के साथ-साथ इस न्यायालय के अन्य निर्णयों के आलोक में, हमारा दृढ़ विचार है कि यदि दो वाद और उसमें दावा की गई राहत कार्रवाई के एक ही कारण पर आधारित हैं तो केवल बाद का वाद सी.पी.सी. के आदेश 2, नियम 2 के तहत वर्जित हो जाएगा। हालांकि, जब कार्रवाई का सटीक कारण, जिस पर प्रतिवादी की ओर से वाद संपत्ति से बेदखल करने के आसन्न खतरे के कारण निषेधाज्ञा के लिए पिछला वाद दायर किया गया था,

तो बल पर और बिक्री समझौते के आधार पर विशिष्ट अनुपालना के लिए बाद के वाद को एक ही वाद हेतुक नहीं माना जा सकता है। तत्काल मामले में, मुकदमों में दोनों पक्षों के अभिवचन से, विशेष रूप से स्थायी निषेधाज्ञा के लिए पहले वाद में वादी द्वारा आरोपित वाद हेतुक और विशिष्ट अनुपालना के लिए वाद में आरोपित वाद हेतुक, यह स्पष्ट है कि वे समान और समान नहीं हैं।

27. उपरोक्त के अलावा, वादी द्वारा दायर निषेधाज्ञा के लिए वाद की शिकायत को पढ़ने पर, यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि वादी ने जानबूझकर अपने दावे के किसी भी हिस्से को इस कारण से छोड़ दिया कि वाद केवल निषेधाज्ञा के लिए था क्योंकि प्रतिवादी की ओर से उसे वाद की संपत्ति से बेदखल करने की धमकी दी गई थी। यह तभी हुआ जब प्रतिवादी ने निषेधाज्ञा के लिए अपने वाद में आवास बोर्ड द्वारा वाद को मुकदमे की संपत्ति के हस्तांतरण का खुलासा किया और उसके बाद वादी द्वारा कानूनी नोटिस के जवाब में प्रतिवादी द्वारा इनकार कर दिया गया, विशिष्ट अनुपालना लिए वाद दायर करने के लिए वाद हेतुक उत्पन्न हुआ।

29. प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर.बालासुब्रमण्यम ने विर्गो इंडस्ट्रीज (इंजीनियरिंग) प्राइवेट लिमिटेड (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा जताया। उक्त मामले में दिए गए निर्णय को देखने के बाद, हमारा विचार है कि उस मामले के तथ्य तत्काल मामले के तथ्यों द्वारा अलग थे। विर्गो इंडस्ट्रीज (उपरोक्त) के मामले में प्रतिवादी द्वारा दो भूखंडों के संबंध में वादी के पक्ष में दो बिक्री समझौतों को निष्पादित किया गया था। निषेधाज्ञा के लिए वादी द्वारा दायर वाद में यह दलील दी गई थी कि प्रतिवादी इस बहाने द्वारा समझौते को विफल करने का प्रयास कर रहा है कि बकाया राजस्व मांग के कारण आबकारी विभाग द्वारा भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध जारी किया जा सकता है। इसके अलावा, प्रतिवादी वाद की

संपत्ति को अलग करके और तीसरे पक्ष को हस्तांतरित करके समझौते को विफल करने की कोशिश कर रहा था। इन तथ्यों पर न्यायालय ने कहाः -

> "5. जबकि मामला इस तरह से स्थित था, दोनों मुकदमों में प्रतिवादी यानी वर्तमान याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत दो अलग-अलग आवेदन दायर करके मद्रास उच्च न्यायालय का रुख किया ताकि 2007 के ओएस संख्या 202 और 203 में इस आधार पर वाद खारिज किए जा सकें कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (संक्षेप में "सीपीसी") के आदेश 2 नियम 2 में निहित प्रावधान दोनों वादों की स्थिरता के लिए एक बाधा है। उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी ने तर्क दिया था कि वादों के दोनों सेटों के लिए वाद हेतुक समान था, अर्थात्, करार दिनांक 27-7-2005 के संदर्भ में बिक्री विलेखों को निष्पादित करने के लिए प्रतिवादी का इनकार या अनिच्छा। इसलिए, वादों के पहले समूह यानी सी.एस. संख्या 831 और 833/2005 को दायर करने के समय, वादी के लिए विशिष्ट अनुपालना की राहत का दावा करने के लिए खुला था। वादी ने उक्त राहत की मांग नहीं की और न ही मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा अवकाश अनुदत्त दी गई। ऐसी परिस्थितियों में, प्रतिवादी-याचिकाकर्ता के अनुसार, वादी द्वारा विशिष्ट अनुपालना के लिए दायर किए गए वाद यानी ओएस संख्या 202 और 203 को आदेश 2 नियम 2 (3) सीपीसी के प्रावधानों के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया था।
>
> XXXXXXX
>
> 13. सी.एस. सं. 831 और 833 ऑफ़ 2005 में दायर किए गए वादपत्रों को पढ़ने से इस आशय के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं कि दिनांक

27-7-2005 की विक्रय करार के निष्पादन के बाद वादी को प्रतिवादी से दिनांक 1-8-2005 का एक पत्र मिला जिसमें यह जानकारी दी गई थी कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग संपत्ति के अलगाव को रोकने के लिए एक नोटिस जारी करने पर विचार कर रहा था। वादी द्वारा प्रतिवादी को चेक द्वारा भुगतान की गई अग्रिम राशि भी वापस कर दी गई थी। वादी के अनुसार यह प्रतिवादी के उपरोक्त रुख से आश्चर्यचकित था जिसने पहले प्रतिनिधित्व किया था कि संपत्ति पर उसका स्पष्ट और विपणन योग्य अधिकार था। वाद के पैरा 5 में, यह कहा गया है कि वादी को उपलब्ध कराए गए दिनांकित 22-8-2005 बोझ प्रमाण पत्र ने वादी का विश्वास प्रेरित नहीं किया क्योंकि उसमें दिनांकित 1-10-2004 की प्रविष्टि थी। इसलिए, वादी ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा शुरू की गई कार्यवाही के संबंध में प्रतिवादी द्वारा किए गए दावे पर गंभीरता से संदेह किया। वाद के उपरोक्त पैराग्राफ में वादी द्वारा यह कहा गया था कि प्रतिवादी "विक्रय करार को रद्द करने और किसी अन्य तीसरे पक्ष को संपत्ति बेचने का बहाना ढूंढ रहा है।" वाद के उपरोक्त पैराग्राफ में, यह आगे कहा गया था कि "इस पृष्ठभूमि में, वादी प्रस्तुत करता है कि प्रतिवादी पक्षों के बीच हुए समझौते को विफल करने का प्रयास कर रहा है।"

14. सी.एस. संख्या 831 और 833 ऑफ़ 2005 में वादी द्वारा किए गए अभिकथन, विशेष रूप से ऊपर निकाले गए अभिवचन, इस बात में कोई संदेह नहीं छोड़ते हैं कि उन तारीखों पर जब सी.एस. संख्या 831 और 833 ऑफ़ 2005 की स्थापना की गई थी, अर्थात्, 28-8-2005 और 9-9-2005, वादी ने स्वयं दावा किया था कि तथ्य और

घटनाएं हुई हैं जो यह तर्क देने का हकदार हैं कि प्रतिवादी का दिनांकित 27-7-2005 करारों का सम्मान करने का कोई इरादा नहीं था। उपरोक्त स्थिति में वादी के लिए यह खुला था कि वह स्थायी निषेधाज्ञा की राहत के साथ विशिष्ट अनुपालना की राहत को शामिल करे जो उपरोक्त दो वादों का विषय बना। दो वादों में दावा किए गए स्थायी निषेधाज्ञा की राहत के लिए आधार ने विशिष्ट अनुपालना की राहत के लिए वाद करने के लिए सी.एस. संख्या 831 और 833 में वादी को पूरा वाद हेतुक प्रस्तुत किया। फिर भी, उक्त राहत को हटा दिया गया और इस संबंध में न्यायालय द्वारा कोई अनुमति प्राप्त या प्रदान नहीं की गई।"

29. तत्काल मामले में, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, निषेधाज्ञा के लिए वाद दायर किया गया था क्योंकि प्रतिवादी की ओर से उसे वाद की संपत्ति से बेदखल करने की धमकी दी गई थी। वादी ने यह आरोप नहीं लगाया कि प्रतिवादी समझौते को विफल करने के लिए संपत्ति को किसी तीसरे पक्ष को हस्तांतरित आदेशने की धमकी दे रहा है।

30. यह सुस्थापित है कि किसी भी निर्णय के अनुपात को उस मामले के तथ्यों की पृष्ठभूमि में समझा जाना चाहिए। प्राथमिकता लागू करने के मामले में लॉर्ड डेनिंग के निम्नलिखित शब्द शाश्त्रीय श्रोत रहे हैं:-

"प्रत्येक मामला अपने स्वयं के तथ्यों पर निर्भर करता है और एक मामले और दूसरे मामले के बीच एक करीबी समानता पर्याप्त नहीं है क्योंकि एक भी महत्वपूर्ण विवरण पूरे पहलू को बदल सकता है, ऐसे मामलों को तय करने में, किसी को मामलों को तय करने के प्रलोभन से बचना चाहिए (जैसा कि कार्डोजो ने कहा है) एक मामले के रंग का

दूसरे के रंग से मिलान करके। इसलिए यह तय करने के लिए कि कोई मामला रेखा के किस तरफ पड़ता है, दूसरे मामले के साथ व्यापक समानता बिल्कुल भी निर्णायक नहीं है।"

31. भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड और एक अन्य बनाम एन.आर. वैरामणि और एक अन्य, (2004) 8 एससीसी 579 के मामले में पृष्ठ 584 पर इस न्यायालय ने कहाः -

"9. न्यायालयों को इस बात पर चर्चा किए बिना निर्णयों पर निर्भरता नहीं रखनी चाहिए कि वास्तविक स्थिति निर्णय की तथ्य स्थिति के साथ कैसे मेल खाती है जिस पर निर्भरता रखी गई है। न्यायालयों के अवलोकन को न तो यूक्लिड के प्रमेय के रूप में पढ़ा जाना चाहिए और न ही किसी क़ानून के प्रावधान के रूप में और वह भी उनके संदर्भ से बाहर लिया जाना चाहिए। इन टिप्पणियों को उस संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए जिसमें वे बताए गए प्रतीत होते हैं। न्यायालयों के फैसलों को क़ानून के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। किसी संविधि के शब्दों, वाक्यांशों और प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए, न्यायाधीशों के लिए लंबी चर्चा शुरू करना आवश्यक हो सकता है, लेकिन चर्चा व्याख्या करने के लिए होती है न कि परिभाषित करने के लिए। न्यायाधीश विधियों की व्याख्या करते हैं, वे निर्णयों की व्याख्या नहीं करते हैं। वे विधियों के शब्दों की व्याख्या करते हैं; उनके शब्दों की व्याख्या विधियों के रूप में नहीं की जानी चाहिए। लंदन ग्रेविंग डॉक कंपनी लिमिटेड बनाम हॉर्टन 1951 एसी 737 (पी. 761 पर एसी) में लॉर्ड मैकडर्मॉट ने कहाः (एएलएल ईआर पी. 14 सी-डी)

"निसन्देह, इस मामले का निपटारा केवल विल्स, जे. के सटीक शब्द की आधार पर नहीं सुलझाया जा सकता, क्योंकि यधपि वे संसद के किसी अधिनियम का हिस्सा हों और उसमे उचित व्याख्या के नियमों को लागू कर रहे हों। इसका उद्देश्य उस सबसे प्रतिष्ठित न्यायाधीश द्वारा वास्तव में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को दिए जाने वाले बड़े महत्व को कम करने के लिए नहीं है।"

32. तत्काल मामले के तथ्यों और साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि विर्गो इंडस्ट्रीज (उपरोक्त) में तय किया गया मुद्दा इस मामले में लागू नहीं होता है।

33. इसके अलावा, इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, हमारी यह सुविचारित राय है कि उच्च न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया है कि मुकदमा आदेश 2 नियम 2 सी. पी. सी. के तहत वर्जित है, कानून में कायम नहीं किया जा सकता है।

34. जैसा कि ऊपर देखा गया है, उच्च न्यायालय ने यद्यपि विचार और निर्णय के लिए विभिन्न बिंदुओं को तैयार किया है, जैसा कि ऊपर उद्धृत किया गया है, लेकिन अपने सही परिप्रेक्ष्य में अन्य बिंदुओं पर विचार नहीं किया है। उच्च न्यायालय, पहली अपील में तथ्यों की अंतिम न्यायालय होने के नाते, उसके द्वारा तैयार किए गए सभी बिंदुओं पर निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। उसी को ध्यान में रखते हुए, मामले को उच्च न्यायालय को वापस भेजने की आवश्यकता है ताकि उनके द्वारा तैयार किए गए अन्य बिंदुओं पर विचार किया जा सके और निर्णय लिया जा सके।

35. उपरोक्त कारण से, सिविल अपील संख्या 4215-4216/2007 को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है और उच्च न्यायालय द्वारा बिंदु संख्या 4 के विरुद्ध दिए

गए फैसले में यह कहा गया कि सीपीसी के आदेश 2 नियम 2 के तहत मुकदमा वर्जित था, इसे खारिज कर दिया गया है। मामले को उसके द्वारा तैयार किए गए अन्य बिंदुओं पर निष्कर्ष दर्ज करके अपील पर निर्णय लेने के लिए उच्च न्यायालय को वापस भेजा जाता है। नतीजतन, प्रतिवादी द्वारा वादी के खिलाफ दायर की गई अन्य संबंधित अपीलों को इस संबंध में उच्च न्यायालय के अगले आदेश तक वाद संपत्ति के कब्जे के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश के साथ निस्तारित किया जाता है।

राजेंद्र प्रसाद

अपीलों का निस्तारण किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता विनायक कुमार जोशी द्वारा किया गया है ।

अस्वीकरण- इस निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।